

आदेश ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या : 19/2025 (धारा 14 सिक्कोरिटाईजेशन)

उज्जीवन स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड, शाखा- सांगानेर, दुकान नं. 3ए, भूतल एवं प्रथम तल, कृष्णा
विहार, टोंक रोड, पुष्प एनक्लेव के पास, सांगानेर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. हमीद अब्दुल उर्फ अब्दुल हमीद उर्फ अब्दुल हमिद पुत्र बशीर मोहम्मद उर्फ बशिर मोहम्मद उर्फ मोहम्मद बशीर,
2. मोहम्मद जाकी पुत्र हमीद अब्दुल उर्फ अब्दुल हमीद उर्फ अब्दुल हमिद,
3. बानो बेगम पत्नी हमीद अब्दुल उर्फ अब्दुल हमीद उर्फ अब्दुल हमिद,
4. जैतून बी उर्फ जैतून बेगम पत्नी बशीर मोहम्मद उर्फ बशिर मोहम्मद उर्फ मोहम्मद बशीर,
पता- मकान नगर परिषद नं. 4021, पतंग वाला का मोहल्ला, जगन्नाथ शाह का रास्ता, रामगंज,
त्रिपोलिया बाजार, जयपुर।



अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation
and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002

उपस्थित :- श्री सत्येन्द्र प्रसाद खोरानिया, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक : 28.01.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.04.2018 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी हाजी अब्दुल हमीद पुत्र हाजी बशीर मोहम्मद एवं जैतून बेगम पत्नी हाजी बशीर मोहम्मद के स्वामित्व की संपत्ति मकान नगर परिषद नं. 4021, पतंग वाला का मोहल्ला, जगन्नाथ शाह का रास्ता, रामगंज, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 150.51 वर्गमीटर को बन्धक रख कर कुल राशि 25,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.05.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 25,00,000/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर




तमिस्त सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्राप्तीगण का ऋण खाता एच बी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 18,39,001/- रूपये की ऋण सुविधा जमा करने हेतु अप्राप्तीगण को दिनांक 18.05.2024 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है, अप्राप्तीगण द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया एवं अप्राप्तीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का शौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्पण में आवश्यक शपथ प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्राप्ती हाजी अब्दुल हमीद पुत्र हाजी बशीर मोहम्मद एवं जैतून बेगम पत्नी हाजी बशीर मोहम्मद के स्वामित्व की बंधक संपत्ति मकान नंबर परिषद नं. 4021, पतंग वाला का मोहल्ला, जगन्नाथ शाह का रास्ता, रामगंज, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 150.51 वर्गमीटर का शौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
आदेश आज दिनांक 28.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर